साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 27 मई -2 जून 2024 वर्ष-10, अंक-6
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

जांच के बाद राज्य सरकार का कड़ा एक्शन | गेहूं घोटाले में शामिल सतना जिला प्रबंधक सस्पेंड

सतना और जबलपुर में गेहूं घोटाला

» फर्जी खरीदी दिखाकर गायब किया 13 ट्रक गेहूं

» जबलपुर के केंद्र में मिला नए गेहूं में घुन लगा गेहूं

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के सतना और जबलपुर में करोड़ों रुपए का गेहूं घोटाला उजागर हुआ है। सतना में 93 लाख रुपए का गेंहू गायब होने का मामला सामने आया है। शासकीय मूल्य पर गेंहू खरीदी केंद्र के लोगों ने जाली कागज तैयार करके 13 ट्रक गेहूं गायब कर दिया। मामला सामने आने के बाद राज्य आपूर्ति निगम के सतना जिला प्रबंधन द्वारा जिले के धारकुंडी थाना में आठ नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

मामला दर्ज होने के बाद जिला प्रबंधक अमित गौड़ को निलंबित कर दिया गया है।

पूरा मामला चित्रकूट अंतर्गत आने वाले ग्राम कारीगोही का है। कारीगोही स्थित जैतमाल बाबा महिला स्व सहायता समूह केंद्र क्रमांक-1 को 2024-25 हेतु समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए अधिकृत किया गया था। इस खरीदी केंद्र से दिनांक 08.05.2024 को 13 ट्रकों में भरकर कुल 3860 क्विंटल गेहूं, जिसकी कीमत 92 लाख 64 हजार रुपए बताई जा रही है। केंद्र के कर्ता धर्ताओं द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर गेहूं को गायब कर दिया गया।

राघव वेयर हाउस में मिला घुन लगा गेहूं

जबलपुर के राघव वेयर हाउस में पुराना घुन लगा गेहूं मिलने की जानकारी मिलने के बाद जबलपुर कलेक्टर ने तुरंत गेहूं की जांच शुरू करवा दी। जिस वेयर हाउस में घुना गेहूं मिला उसमें जैसे-जैसे अंदर का गेहूं निकाला गया तो वह और ज्यादा खराब था। कलेक्टर ने कई टीम बनाकर ना केवल राघव वेयर हाउस बल्कि जबलपुर जिले के सभी खरीदी झकेन्द्रों के जांच के आदेश दे दिए हैं।

गेहूं की बोरों से टैग गायब

जबलपुर में एक बार फिर गेहूं खरीदी में यहां घोटाला सामने आया है। घोटाले में नए गेहूं में पुराना घुन लगा गेहूं मिला दिया गया है और गेहूं की बोरों से टैग गायब कर दिए गए हैं। घुना हुआ पुराना गेहूं राघव वेयर हाउस से मिला है। कलेक्टर के आदेश के बाद पूरे जिले के गेहूं की जांच की जा रही है और जहां कहीं भी घुना हुआ गेहूं पाया जाएगा वहां किसानों का भुगतान रोक दिया जाएगा। तय किया जा रहा है कि यह घुना हुआ खराब गेहूं किसने बेचा है। कलेक्टर ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड करते हुए हिदायत दी है कि गेहूं की बोरों से टैग नहीं निकाला जाए।

छह करोड़ के गेहूं में घुन

राघव वेयर हाउस में यह गेहूं रखा हुआ था उसमें 6 करोड़ 19 लाख रुपए में से 4 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किसानों को हो चुका था, लेकिन अभी जिन किसानों को भुगतान नहीं हुआ है उनके भुगतान पर रोक लगा दी गई है। और जिन्हें भुगतान हो गया है और किसानों ने यदि बैंक से पैसा नहीं निकला है तो उसे पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है।

घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद जांच कमेटी गठित कर जांच कराई गई। जांच के बाद पूरा मामला सामने आ गया कि किस प्रकार खरीद केंद्र के कर्ता धर्ताओ द्वारा फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर गेंहू गायब कर दिया गया।

अनुराग वर्मा, कलेक्टर, सतना

राज्य आपूर्ति निगम के सतना जिला प्रबंधक द्वारा आठ नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा पूरे मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर दी गई है।

विक्रम सिंह, एएसपी, सतना

घोटाले में कई कर्मचारी, समिति प्रबंधक, सरवेयर दोषी हैं। सभी पर कार्रवाई भी की जाएगी। गोदाम के मालिक की भी भूमिका संदिग्ध है। जांच की जा रही है। चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।

दीपक सक्सेना, कलेक्टर, जबलपुर

समर्थन मूल्य पर टागरेट से 33 लाख टन पीछे

मप्र में गेहूं खरीदी का लक्ष्य पाना टेढ़ी खीर

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। दो बार तिथि में वृद्धि करने के बाद भी अब तक 47 लाख टन गेहूं का उपार्जन ही हो पाया है यानी लक्ष्य से 33 लाख टन कम। इसका कारण बाजार में अधिक मूल्य मिलना और उपज रोककर रखना भी है। दरअसल, इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण उपज प्रभावित हुई है। इसके चलते माना जा रहा है कि एक-दो माह बाद गुणवत्तायुक्त गेहूं की कीमत और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने भी अधिकारियों से उपार्जन की स्थिति की जानकारी ली। प्रदेश में इस बार समर्थन मूल्य 80 लाख टन गेहूं के उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। अतिवर्षा के कारण उपार्जन कार्य प्रभावित हुआ तो सरकार ने दो बार उपार्जन की अवधि बढ़ाई गई ताकि जो किसान उपज बेचने से रह गए, उन्हें अवसर मिल सके। इसके बाद भी अब तक 47 लाख टन गेहूं का उपार्जन ही हो पाया है। इसमें भी साढ़े तीन लाख टन गेहूं वो है जिसकी चमक वर्षा से प्रभावित हुई। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 50 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं खरीदने की अनुमति प्रदेश को दी है।

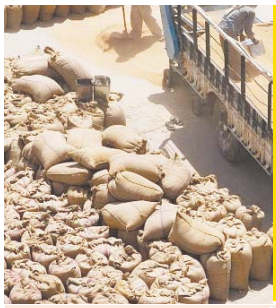

» सीएम ने लिया फीडबैकः अब 25 जून तक खरीदी

» 80 लाख टन गेहूं के उपार्जन का सरकार ने रखा लक्ष्य

» बाजार में अधिक दर मिलने के कारण कम बेच रहे किसान

» समर्थन मूल्य के साथ ही बोनस राशि के भुगतान भी हो रहा

25 जून तक होगी गेहूं की खरीदी

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे गेहूं उपार्जन कार्य के संबंध में भी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में 15 मार्च से गेहूं उपार्जन का कार्य चल रहा है। सप्ताह में सभी दिन यह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सभी संभागों में 25 जून तक गेहूं उपार्जन का कार्य किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्हें समर्थन मूल्य के साथ ही बोनस राशि के भुगतान की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है।

किसानों ने रख लिया गेहूं

कृषि और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसानों को बाजार में गेहूं की कीमत अच्छी मिल रही है। इस कारण समर्थन मूल्य पर उपार्जन कम हो रहा है। किसानों ने गुणवत्तायुक्त गेहूं भी रोककर रख लिया है ताकि जब कीमत और बढ़े तो उसे बेच सकें।

मंत्री प्रह्लाद पटेल के घर नीम का पेड़ दे रहा आम का फल

बरसों पहले की गई क्राप्टिंग के नतीजे अब आए सामने

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल के भोपाल स्थित बंगले में लगा एक पेड़ सुर्खियां बटोर रहा है। खासियत यह है कि नीम का पेड़ है लेकिन, उसमें फल आम के लगते हैं। दरअसल, ये क्राप्टिंग का नमूना था। मंत्री ने कैरी तोड़ी और चखी तो उसमें नीम का कड़वापन भी नहीं था। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह पेड़ 20 से 25 साल पुराना है। मंत्री ने कर्मचारियों से इस पेड़ का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस खास पेड़ का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इसका वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि भोपाल निवास पर नीम के वृक्ष पर आम के फल को नजदीक से जाकर देखा तो मन गदगद हो गया। किसी हुनरमंद बागवान ने वर्षों पहले यह प्रयोग किया होगा जो अचंभे से कम नहीं है।

सुधार कर सभी किसानों को जल्द भुगतान का प्रयास

गड़बड़ी का राजफाश किसानों के बैंक खातों में उपज का भुगतान करने के दौरान ईपीओ फेल होने के बाद हुआ

खातों में गड़बड़ी!3.5 करोड़ रुपए का अटका भुगतान

नर्मदापुरम। जागत गांव हमार

जिले में समर्थन मूल्य पर उपज बेचने वाले 488 किसानों के बैंक खातों में गड़बड़ी सामने आई है। इस वजह से किसानों का करीब 3.5 करोड़ का भुगतान असफल हुआ है। भुगतान अटकने से किसानों को परेशानी हो रही है। गड़बड़ी का राजफाश किसानों के बैंक खातों में उपज का भुगतान करने के दौरान ईपीओ फेल होने के बाद हुआ। इस वजह से किसानों के खातों मे उपज की भुगतान राशि ट्रांसफर नहीं हो सकी। किसानों को खाद्य विभाग ने चिह्नित कर जिला सहकारी बैंक को सूची भेजी। सूची मिलते ही बैंक प्रबंधन ने खातों को तत्काल सुधारने का कार्य शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों के बैंक खातों को सुधार कर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। अधिकतम खाते सुधार दिए गए हैं।

गड़बड़ी का यह कारण- जिला सहकारी बैंक विपणन कक्ष प्रभारी आनंद यादव ने बताया कि जिले के करीब 488 किसानों के बैंक खाते व आइएफएससी कोड आदि गलत फीड होने से उपज का भुगतान असफल हो गया था। जिसके बाद बैंक मुख्यालय के मार्गदर्शन में शाखा स्तर से किसानों से संपर्क कर सतत सुधार किया गया। करीब 420 कृषकों के बैंक खातों को सुधार कर भुगतान की कार्रवाई कराई गई है। अभी 68 किसानों के बैंक खाते सुधार के लिए शेष है। सही खाते नंबर फीड कर शीघ्र सुधार किया जा रहा है।

इस वजह से अटकी राशि

किसानों ने समर्थन मूल्य पर उपज बेचने पंजीयन कराए थे। कुछ किसानों ने कियोस्क व मोबाइल से भी पंजीयन किए थे। उस दौरान कृषकों के बैंक खाते नंबर व आइएफएससी कोड गलत फीड होने से यह गड़बड़ी हुई। कुछ मामलों में बैंक खाते का संचालन नियमित नहीं होने से खाते बंद हो गए। इसके अलावा ईकेवायसी अपडेट, मृत खातेदार, क्रेडिट लिमिट जैसी समस्याओं की वजह से किसानों को उपज बेचने के बाद राशि ट्रांसफर नहीं हो सकी। समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के बाद भुगतान नहीं मिलने से परेशान किसान अपना खाता नंबर सुधराने सोसायटी व बैंक के चक्कर लगा रहे हैं।

जिला सहकारी बैंक ने सक्रियता से सुधारे खाते

किसानों के गलत बैंक खातों की जानकारी लगते ही जिला सहकारी बैंक ने सक्रियता दिखाई। खाद्य विभाग से सूची मिलते ही प्रबंधन ने समितियों के माध्यम से तत्काल किसानों से संपर्क कर सही खाते की पासबुक से मिलान कर खाते नंबर अपडेट किए। बैंक अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द समस्या को दूर कर लिया जाएगा। जिले में किसानों को भुगतान बेहतर तरीके से हुआ है।

- जिन किसानों के बैंक खातों में गड़बड़ी है उन किसानों से संपर्क कर खातों में सुधार करवाया जा रहा है। साथ ही बैंक खातों में सुधार कर भुगतान कराया जा रहा है। अधिकतर किसानों के खाते सुधार कर दिए गए हैं। शेष किसानों के खाते भी शीघ्र सुधार किए जा रहे हैं।

शिवम मिश्रा, महाप्रबंधक,
जिला सहकारी बैंक,नर्मदापुरम

31 मई तक होगी समर्थन पर खरीदी

जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तिथि बढ़ा दी गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने शुक्रवार को आदेश पत्र जारी कर 31 मई तक गेहूं उपार्जन कार्य के आदेश दिए हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय से शेष रहे किसान अवसर का लाभ उठाते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय कर सकते हैं। खरीदी की तिथि बढ़ाने से एक बार फिर मंडियों में किसानों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जिले की कई मंडियों में खरीदी हो चुकी है। वेयरहाउस में अनाज पहुंचा दिया गया है साथ ही परिवहन भी किया जा रहा है।

तापमान बढ़ने से पड़ सकता है विपरीत असर

मई के बाद ही किसान करें कपास की बोवनी, मिलेगा अच्छा उत्पादन

खरगोन। जागत गांव हमार

जिले में खरीफ की फसल में गर्मी में कपास की बोवनी की तैयारी चल रही है। निमाड़ अंचल में कृषकों द्वारा कपास की बोवनी अक्षय तृतीया से करने की परंपरा रही है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि वर्तमान में जिले का तापमान सामान्य से अधिक है और गर्म हवाएं भी चल रही हैं। इससे कपास बीज का अंकुरण एवं पौधों की बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिससे फसल की स्थिति ठीक नहीं रहती है। कपास की बोवनी 25 मई या तापमान कम होने के बाद ही करें। ऐसा करना से उपज बेहतर हो सकती है। इसके अलावा व्यापारियों से कृषक खाद, बीज का पक्का बिल मांगें। कृषि उपसंचालक एमएल चौहान ने बताया कि सभी कृषकों कपास बीज के पैकेट पंजीकृत विक्रेताओं से शासन द्वारा निर्धारित बीजी-1 635 रुपए एवं बीजी-2 864 रुपए प्रति पैकेट (475 ग्राम) दर पर ही क्रय करें। समस्त क्रय किए गए आदान सामग्री का पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें। किसी भी बीज विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर विक्रय किया जाता है, तो उनकी शिकायत संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को उनके मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं।

इनसे करें शिकायत

खरगोन एवं गोगांवा विकासखंड के कृषक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गिरधारी भावर, सेगांव एवं भगवानपुरा के कृषक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राजाराम चौहान, बड़वाह एवं कसरावद के कृषक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीएस सेंगर, भीकनगांव विकासखंड के कृषक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रामलाल मोरे, झिरन्या विकासखंड के कृषक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिहारीलाल डावर व महेश्वर विकासखंड के कृषक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रामलाल वर्मा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन किया गया। इसमें 07282-466865 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। कृषक रासी कपास किस्म 659 का वितरण अनाज मंडी प्रांगण से बीज उपलब्धता अनुसार पावती के आधार पर दो पैकेट प्रति पावती अनुसार जिले के बीज विक्रेताओं के माध्यम से किया जाएगा। साथ किसानों से कहा है कि क्रय किए जा रहे कपास बीज एवं अन्य कृषि आदान का पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें।

बोनस राशि मिलने से हुए खुश

14 हजार किसानों ने बेचा 95 हजार टन गेहूं

कटनी। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों ने गेहूं खरीदी केंद्रों में जमकर अपनी उपज बेची है। अब तक 95 हजार मैट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी हो चुकी है। कटनी जिले की 6 तहसील में 85 गेहूं खरीदी केंद्र प्रशासन द्वारा बनाए गए थे, जिसमें करीब 14 हजार किसानों ने अब तक 95 हजार मैट्रिक टन गेहूं बेचा है। हालांकि, शुरुआती दौर में किसानों ने उचित रुझान नहीं दिखाया था। इसकी वजह शासन द्वारा 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी थी। लेकिन, जैसे ही बोनस राशि 125 रुपए बढ़ाई गई तो किसानों ने केंद्रों में गेहूं बेचने के स्लॉट बुक करते हुए अलग-अलग केंद्रों में पहुंचकर अपनी उपज बेचते हुए शासन की योजनाओं का लाभ उठाया है। जिले में गेहूं खरीदी के मामले पर सबसे अव्वल ढीमरखेड़ा समिति रही है, जिसने महज 2 केंद्रों से ही 50 हजार क्विंटल से ज्यादा की खरीदी कर डाली। वहीं बड़वारा और रीठी इन मामलों में काफी पीछे रह गईं। समिति प्रबंधक संजय ने बताया कि क्षेत्र में गेहूं की पैदावार काफी है। लेकिन, किसान अपना माल मंडी में बेचने जा रहे थे, जिसके बाद शासन द्वारा 125 रुपयों का बोनस बढ़ाया गया और हमारे द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए किसानों के लिए पीने के पानी, बैठने और उनकी उपज जल्द से जल्द तुलवाई करवाने समेत अन्य व्यवस्था बनाई गईं। जिससे किसानों ने आकर्षित खरीदी केंद्रों पर आकर गेहूं बेचा, इसलिए हम जिले में सबसे ज्यादा खरीदी कर सके हैं। फिलहाल गेहूं खरीदी का कार्य अपने अंतिम चरण पर है, संभावना है कि जिले में 100 हजार मैट्रिक टन खरीदी हो सकती है।

ड्रोन खाद और को-आपरेटिव इफको उपलब्ध करा रहा, किसानों का समय और लागत दोनों की बचत

जिले के दस हजार से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा

फसलों पर ड्रोन से छिड़काव, मिलेंगे तीन ड्रोन बालाघाट में तकनीकी रूप से दक्ष की तलाश

बालाघाट। जागत गांव हमार

किसानों को कम लागत और कम समय में फसलों पर खाद और पेस्टीसाइड के छिड़काव के लिए तीन ड्रोन मिलेंगे। कृषि विभाग ने बालाघाट, किरनापुर और लांजी में संचालित एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन) को ड्रोन संचालित करने वाले जानकार हितग्राही चुन लिए गए हैं। इसके अलावा वारासिवनी, खैरलांजी और कटंगी में तकनीकी रूप से दक्ष हितग्राही की तलाश जारी है। कृषि उप संचालक राजेश खोब्रागढ़े ने बताया कि यह ड्रोन खाद और को-आपरेटिव क्षेत्र की इफको द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों को खेती में राहत के साथ तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देना मकसद है। ड्रोन से दवाइयों के छिड़काव से किसानों का समय और लागत दोनों की बचत होती है। जिलेभर में संचालित किसानों के समूहों को यह ड्रोन उपलब्ध कराई जा रही है।

पूर्व में परसवाड़ा और लालबर्रा के एफपीओ को यह ड्रोन उपलब्ध कराई गई थी, जिसकी मदद से इन एफपीओ से जुड़े किसानों के खेतों में दवाइयों का छिड़काव किया गया था। तीन ड्रोन मिलने से तीन तहसीलों के करीब दस हजार से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। खासकर उन किसानों को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा, जो बड़े रकबे में खरीफ की फसल लगाते हैं और दवाइयों के छिड़काव के लिए पारंपरिक तरीका अपनाते हैं। इसे लेकर विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर ड्रोन की कार्यप्रणाली, क्षमता आदि की जानकारी दी जा रही है।

रबी में नहीं हुआ ज्यादा उपयोग

पूर्व में बालाघाट जिले को कंपनी ने परसवाड़ा और लालबर्रा में संचालित किसानों के समूह यानी एफपीओ को ड्रोन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन रबी में खेती का कम रकबा और चना, मसूर, गेहूं जैसी फसलों में खाद या दवा के छिड़काव की कम जरूरत के कारण किसानों ने इसमें रुचि नहीं ली, लेकिन विभाग का मानना है कि खरीफ सीजन में जहां खेती का रकबा बढ़ा होता और साथ ही धान जैसी महत्वपूर्ण फसल में दवाइयों के छिड़काव की अधिक जरूरत के कारण किसान इसमें रुचि लेंगे। श्री खोब्रागढ़े ने बताया कि बालाघाट, किरनापुर और लांजी में ड्रोन के संचालन के लिए हितग्राहियों का चुनाव कर लिया गया है। इसके लिए उनकी ड्रोन को संचालित करने की दक्षता, तकनीकी ज्ञान और अभिरुचि को ध्यान में रखा गया है। हालांकि, छोटे किसानों में इस पहल को लेकर जागरूकता की कमी देखी जा रही है। जिसे लेकर कृषि विभाग लगातार शिविर आयोजित कर रहा है।

शिविरों में दे रहे प्रशिक्षण, बताए फायदे

किसानों को उन्नत तकनीकीयुक्त आधुनिक कृषि की ओर आकर्षित करने के मकसद से किसानों को शिविरों में ड्रोन की मदद से तरल उर्वरक एवं कीटनाशक का छिड़काव करना सिखाया जा रहा है। इसके लिए ड्रोन की मदद से किसानों को खेतों में जाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उन्नत आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को ड्रोन तकनीक से अवगत कराने के साथ इसकी कीमत से लेकर फायदों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। अत्याधुनिक ड्रोन की 12 से 14 लाख रुपए है। इसमें सामान्य वर्ग के कृषकों को 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु व सीमांत किसान, महिला किसान को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है तथा किसान लगभग चार से पांच लाख रुपये की छूट पर ड्रोन खरीद सकता है। ड्रोन से दस मिनिट में लगभग एक एकड़ जमीन पर आसानी से छिड़काव किया जा सकता है।

- जिले के किसानों को उन्नत और तकनीकी खेती से जोड़ने के लिए ड्रोन से तरल खाद व कीटनाशक के छिड़काव दिया गया है। इसके लिए अब तीन ड्रोन उपलब्ध होंगे। इसके लिए तकनीक रूप से दक्ष हितग्राही को उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा मिलेगा, बल्कि कम लागत और कम समय में उन्नत खेती करेंगे।

राजेश खोब्रागढ़े, उप संचालक
कृषि विभाग, बालाघाट

रतलाम में सड़क पर मिर्च फेंक कर किया प्रदर्शन

मिर्च की गिरती कीमतों से संकट में मप्र के किसान

भोपाल। जागत गांव हमार

मिर्च की गिरती कीमतों से परेशान मध्य प्रदेश के किसानों ने रतलाम और आसपास के इलाकों में गत दिवस विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर पहले प्याज फिर लहसुन की गिरती कीमतों के कारण किसान पहले से ही संकट में हैं। अब हरी मिर्च की घटती कीमतों ने उन्हें और परेशान कर दिया है। इसके कारण किसान अब विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी विरोध के तहत किसानों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए हरी मिर्च से भरे पैकेट को सड़कों पर फेंक कर प्रदर्शन किया। किसानों के विरोध का यह तरीका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। रतलाम के परशुराम विहार कॉलोनी के बीच में हरी मिर्च की कम कीमत से परेशान होकर किसान गुस्से में आ गया है। वायरल वीडियो में दिखाया कि कम कीमत से परेशान किसान अपनी मिर्च के बैग को एक के बाद एक सड़कों पर फेंक रहा है। व्यापारी किसानों ने 6-7 रुपए प्रति किलोग्राम की मामूली कीमत पर मिर्च खरीद रहे हैं। जबकि बाजार में फिलहाल यह 30-40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है।

मंडी के रतलाम के सब्जी मंडी के व्यापारियों ने बताया कि मिर्च का थोक भाव फिलहाल 10-12 रुपए किलोग्राम चल रहा है। हालांकि यह कीमत किसानों के लिए संतोषजनक नहीं है। मिर्च फेंककर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान सरकार और प्रशासन से मिर्च की उचित कीमत दिलाने की मांग कर रहे हैं। ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके और उनकी स्थिति में सुधार हो सके।

ठगा महसूस कर रहे किसान

खरीद और बिक्री की कीमतों के बीच हो रहे इस भारी अंतर के कारण किसान खुद को ठगा हुआ और असहाय महसूस कर रहे हैं। इसके कारण किसान समुदाय के अंदर काफी गुस्सा और उनमें काफी नाराजगी भी है। किसानों का कहना है कि वो इतनी मेहनत करके खेती करते हैं। गर्मी के मौसम में पानी के अभाव में उन्होंने मेहनत करके खेती की पर अब उन्हें अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। वर्तमान में मिर्च किसान जिस परेशानी से गुजर रहे हैं उससे प्याज और लहसुन को किसानों दारा हाल ही में किए गए संघर्ष कि याद आती है। रतलाम जिले के किसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि इससे पहले प्याज और लहसुन की कीमतें भी किसानों को नहीं मिल पाई है।

-छह अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के पैनल ने पुरस्कार के विजेता को चुना

पर्यावरण-कृषि पर शोधः आईआईटी इंदौर की मुखर्जी को ग्लोबल अवॉर्ड

-यह सम्मान प्राप्त करने वाले प्रो. मुखर्जी देश के एकमात्र वैज्ञानिक

इंदौर। जागत गांव हमार

माइक्रो इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेहतर शोध कार्यों के लिए आईआईटी इंदौर के प्रो. शैबाल मुखर्जी को पहली बार ग्लोबल 2024 माइक्रो इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग जर्नल मिडिल कैरियर इन्वेस्टिगेटर अवार्ड और लेक्चररशिप प्राप्त हुई है। आईआईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत प्रो. मुखर्जी को यह सम्मान पर्यावरण निगरानी से लेकर कृषि और स्वास्थ्य देखभाल तक के अनुप्रयोगों के लिए ए आई - आई ओ टी आधारित क्वांटम उत्पादों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला है। एल्सेवियर की जर्नल प्रकाशक चेन लिन की निगरानी में छह अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक पैनल ने इस पुरस्कार के विजेता का चयन किया है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले प्रो.मुखर्जी देश के एकमात्र विज्ञानी हैं। प्रो. मुखर्जी के नाम आईआईटी इंदौर में सबसे ज्यादा नौ पेटेंट हैं। जबकि चार शोध कार्य पेटेंट के लिए फाइल किए जा चुके हैं। प्रो. मुखर्जी के 250 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं।

शोध से इन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

प्रो. मुखर्जी के निर्देशन में तैयार की गई प्रौद्योगिकी कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में काफी उपयोगी साबित होगी। प्रो. मुखर्जी ने वर्ष 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। सिंगापुर में 15 से 18 जुलाई को आईईईई इंटरनेशनल सिंपोजियम आन द फिजिकल एंड फेल्योर एनालिसिस आफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स (आइपीएफए) 2024 के 31वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। यहां प्रो. मुखर्जी को प्रतिष्ठित ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार माइक्रो नैनो-इलेक्ट्रानिक सामाग्रियों, उपकरणों और सर्किटों के निर्माण और शोध के क्षेत्र में कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है।

महिला स्वास्थ्य के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस (28 मई) पर विशेष

पारिवार खुशहाल तभी होगा, जब स्वस्थ रहेंगी स्त्रियां

मुकेश कुमार शर्मा
एक्जेक्युटिव डायरेक्टर
पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया

स्वस्थ जिन्दगी हर किसी की पहली जरूरत होती है, लेकिन बहुत से घरों में आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता में नहीं रखा जाता है, जो कि अत्यंत ही विचारणीय विषय है। महिला का पूर्ण स्वस्थ होना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि वह अस्वस्थ हो जाए तो घर के बच्चों से लेकर बड़े तक सभी प्रभावित होते हैं।

महिला बिस्तर पर पड़ जाए तभी डाक्टर के पास ले जाएं जैसी सोच को बदलना होगा और महिला को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए हर जरूरी पहलू पर गंभीरता से विचार करना होगा। इसी सोच को परवान चढ़ाने के लिए हर साल 28 मई को महिला स्वास्थ्य के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर भी खुलकर बात करने की जरूरत है ताकि महिला स्वतंत्र रूप से यह निर्णय ले सके कि उसे कब और कितना बच्चा चाहिए।

प्रजनन स्वास्थ्य किसी भी महिला का भारतीय संविधान द्वारा दिया गया वह अधिकार है जिसमें समानता एवं शिक्षा का अधिकार, सही उम्र में विवाह का अधिकार, परिवार नियोजन अपनाने का अधिकार, महिला को बच्चा कब और कितना चाहिए यह निर्णय लेने का अधिकार तथा हिंसा मुक्त एवं पोषणयुक्त खुशहाल जीवन जीने का अधिकार शामिल है। अनचाहा गर्भधारण महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने के साथ ही जान को जोखिम में डालने का काम करता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद बास्केट ऑफ़ च्वाइस में से अपना मनपसन्द गर्भ निरोधक विकल्प चुनें और अनचाहे गर्भ से बचकर स्वस्थ रहें और घर में खुशहाली लाएं। इसमें पति से लेकर माता-पिता, सास-ससुर और परिवार के अन्य बड़े सदस्यों की भी अहम भूमिका हो सकती है।

महिला स्वास्थ्य के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस को हर साल मनाने का मूल उद्देश्य महिलाओं को उनकी सेहत से जुड़े मुद्दों के बारे में पूर्ण रूप से शिक्षित करने के साथ ही उन्हें हर क्षेत्र में सशक्त बनाना है।

महिलाओं को भेदभाव, घरेलू हिंसा, जबरदस्ती और उपेक्षा से बचाने के बारे में इस दिवस पर हर किसी का ध्यान आकर्षित किया जाता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी जरूरी है। इस दिवस पर संकल्प लेने की जरूरत है कि महिलाओं तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को आसान बनायेंगे। सुरक्षित एवं कानूनी गर्भपात के बारे में शिक्षित बनाएंगे । युवाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के साथ ही एचआईवी/एड्स के प्रति भी जागरूकता लायेंगे।

इस दिवस को मनाने की सार्थकता तभी है जब स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में लैंगिक असमानता को पूरी तरह से दूर करते हुए महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य, मातृ कल्याण और यौन व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के प्रति सशक्त बनाया जाए। महिलाओं और लड़कियों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने के लिए उचित और समान अवसर दिया जाए और व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराया जाए। घरेलू हिंसा और संभावित मानव तस्करी पर चर्चा हो । कम उम्र में शादी और शादी के तुरंत बाद गर्भ धारण जैसी सोच को बदला जाए। करियर में उन्नति के लिए समान रास्ते विकसित करने के साथ ही वेतन असमानता को दूर करने की तरफऔर पयाज़्त प्रयास हों।

देश में आज भी 15 से 49 वर्ष आयुवर्ग की कम ही महिलाएं यौन संबंधों, गर्भनिरोधक साधनों के इस्तेमाल और यौन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अपनी पसंद को प्राथमिकता दे पाती हैं। इस तरह इस आयु वर्ग की बहुत सी महिलाओं के पास अब भी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस गंभीर विषय पर एकजुटता के साथ चर्चा की जाए और जागरूकता के उपायों पर विचार किया जाए ।

कार्यशालाओं आदि के माध्यम से गर्भपात से जुड़ीं भ्रांतियों को दूर किया जाए। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों का इस्तेमाल करते हुए महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता लायी जाए। सफल महिलाओं को सच्ची कहानियों का माध्यम बनाया जा सकता है, जिससे उनके संघर्ष से लेकर सफलता के पायदान को विस्तार से बताया जाए। यह कहानियाँ प्रेरक की भूमिका निभा सकती हैं । प्रचार-प्रसार के अन्य तरीकों जैसे- पोस्टर-बैनर, इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि का भी सहारा लिया जा सकता है। ज्ञात हो कि वर्ष 1987 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार इस

पर्यावरण के लिए खतरा, अनियेजित शहरीकरणः आईआईटी

भारतीय शहरों में बढ़ता तापमान अपने साथ नई चुनौतियां भी पैदा कर रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हाल ही में दिल्ली में सामने आया जब भीषण गमीज़ और लू के चलते गमिज़्यों की छुट्टियों के लिए स्कूलों को जल्द बंद कर देना पड़ा। गौरतलब है कि दिल्ली में पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में भारतीय शहरों में तापमान इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, क्या शहरों में तेजी से बढ़ता कंक्रीट, पेड़ो और जलाीतों का होता विनाश इसके लिए जिम्मेवार है। इसमें कोई शक नहीं की शहर जलवायु परिवतज़्न और शहरीकरण के संयुक्त प्रभावों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। लेकिन शहरीकरण किस हद तक बढ़ते तापमान और गमीज़ के लिए जिम्मेवार है, इसे समझना भी बेहद जरूरी है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भुवनेश्वर से जुड़े शोधकर्ताओं का दावा है कि अकेले शहरीकरण ने भारतीय शहरों में गर्मी को 60 फीसदी तक बढ़ा दिया है। उनके मुताबिक पूर्वी भारत के टियर-2 शहर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर में शहरीकरण ने वार्मिंग में 90 फीसदी का योगदान दिया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर से जुड़े शोधकर्ता सौम्या सत्यकांत सेठी और वी विनोज द्वारा किए इस अध्ययन के नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर सिटीज में प्रकाशित हुए हैं। देखा जाए तो जिस तरह से शहरों में पेड़ों, हरित क्षेत्रों, झीलों को पाट कर कंक्रीट का जंगल बढ़ रहा है। उसका खामियाजा शहरों में आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं पेड़ों की ठंडी छांव की जगह जिस तरह एयर कंडीशन जैसी मशीनों पर निर्भरता बढ़ रही है, वो भी भारतीय शहरों में बढ़ती गर्मी की वजह बन रही है।

अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पिछले दो दशकों के दौरान भारत के 141 प्रमुख शहरों में बढ़ते तापमान पर शहरीकरण और स्थानीय जलवायु में आते बदलावों के प्रभावों का अध्ययन किया है। उन्होंने इन शहरों की सीमाओं को मैप करने के लिए उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया है।

पेड़ों को काट, झीलों को पाट, बिछ रहा कंक्रीट का जंगलः इन शहरों में बढ़ते तापमान के रुझानों को जानने के लिए 2003 से 2020 के बीच नासा के मोडिस एक्वा उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों की मदद ली है। तापमान के यह आंकड़े भूमि की सतह के पास बढ़ते तापमान के रुझानों को दर्शाते हैं। इनकी मदद से शोधकर्ताओं ने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के रुझानों की तुलना की है।

शोधकर्ताओं का मानना है कि जहां ग्रामीण और गैर-शहरी क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के पीछे की वजह क्षेत्रीय तौर पर जलवायु में आता बदलाव है। वहीं शहरों में बढ़ते तापमान के लिए जलवायु परिवतज़्न और शहरीकरण दोनों ही जिम्मेवार हैं। इसका मतलब है कि शहरों में बढ़ता कंक्रीट और भूमि उपयोग में आता बदलाव अतिरिक्त गर्मी पैदा कर रहा है। बढ़ता शहरीकरण ऐसे अपरिवर्तनीय इंसानी हस्तक्षेपों में से एक है, जो बड़ी तेजी से प्राकृतिक आवासों को निगल रहा है। यह सही है कि इसने सामाजिक आर्थिक बदलावों को गति दी है, लेकिन साथ ही इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो यह शहर भूमि के केवल एक फीसदी हिस्से पर मौजूद हैं, लेकिन साथ ही यह दुनिया की आधी आबादी का घर हैं। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की 68 फीसदी आबादी शहरों में रह रही होगी। सामाजिक उन्नति का संकेत माने जाने के बावजूद तेजी से अनियोजित शहरीकरण ने दुनिया के कई हिस्सों में पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इससे इंसान भी सुरक्षित नहीं है।

इंसान स्वयं लिख रहा विनाश की पटकथाः भारतीय शहर भी इन बदलावों से परे नहीं है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो 2050 तक शहरी आबादी दोगुनी हो सकती है। अनुमान है कि तब भारत में करीब 80 करोड़ लोग शहरों में रह रहे होंगें। नतीजन यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहरी क्षेत्र बन जाएगा। अनुमान है कि भारत 2050 तक ऊर्जा मांग में सबसे अधिक वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था भी होगा। इस स्तर पर होते विकास का समर्थन करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निमाज़्ण किया जाएगा, जो उत्सर्जन में वृद्धि की वजह बनेगा। इसका असर स्थानीय और क्षेत्रीय जलवायु पर भी पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि भारत पहले ही जलवायु में आते बदलावों के प्रति बेहद संवेदनशील है। यही वजह है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने भी भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली चरम मौसम घटनाओं के मामले में सातवें सबसे प्रभावित देश के रूप में दर्शाया है। वैज्ञानिक अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं भारत जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर देशों में से एक होगा, खासकर भारतीय शहर, तेजी से होते शहरीकरण और जलवायु जोखिमों के चलते विशेष रूप से असुरक्षित होंगे।

हालांकि शहरों में बढ़ती गर्मी में शहरीकरण की कितनी भूमिका है यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। यही वजह है कि अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अलग-अलग अध्ययन किया है। गौरतलब है कि इससे पहले किए एक अन्य अध्ययन में पूर्वी भारत के शहर भुवनेश्वर में बढ़ती गर्मी में शहरीकरण के प्रभावों को उजागर किया था। अध्ययन के मुताबिक भुवनेश्वर में रात में भूमि की सतह के तापमान में होने वाली 70 से 80 फीसदी वृद्धि के लिए शहरीकरण जिम्मेवार है।

वहीं इस नए शोध में शोधकर्ताओं ने देश के 141 शहरों में बढ़ते तापमान और शहरीकरण का अध्ययन किया है। इसके नतीजे दर्शाते हैं कि दिल्ली, मुंबई की तुलना में पूर्वी भारत के टियर-2 शहरों में बढ़ती गर्मी में शहरीकरण की भूमिका कहीं ज्यादा होगी। आंकड़ों के मुताबिक जहां भुवनेश्वर में शहरीकरण के चलते गर्मी में 90 फीसदी का इजाफा हुआ है। वहीं जमशेदपुर में यह आंकड़ा 100 फीसदी दर्ज किया गया।

इसी तरह रायपुर में 77.7 फीसदी, पटना में 67.2 फीसदी, इंदौर में 66.9 फीसदी, भिलाई में 65.4 फीसदी, औरंगाबाद में 61.8 और पुणे के बढ़ते तापमान में 61.2 फीसदी के इजाफे के लिए शहरीकरण जिम्मेवार रहा। कुल मिलकर देखें तो अध्ययन किए गए भारतीय शहरों में शहरीकरण ने बढ़ते तापमान में औसतन 0.2 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक का योगदान दिया है।

महीने में पांच ग्राम माइक्रो प्लास्टिक खा रहे हैं लोग

कॉर्नेल शोधकर्ताओं द्वारा 109 देशों में माइक्रोप्लास्टिक को खाने या निगले जाने की जांच-पड़ताल की गई है। अध्ययन के अनुसार, इंडोनेशिया, मलेशिया और फ़िलीपींस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लोग माइक्रोप्लास्टिक निगलने की वैश्विक प्रति व्यक्ति सूची में शीषज़ पर हैं। जबकि चीन, मंगोलिया और यूनाइटेड किंगडम सबसे अधिक माइक्रोप्लास्टिक के वातावरण में सांस लेने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर हैं।

एनवायर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन, मौजूदा आंकड़ों के मॉडल पर आधारित है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि अनुपचारित प्लास्टिक मलबे के खराब होने और पर्यावरण में फैलने के कारण मनुष्य अनजाने में कितना माइक्रोप्लास्टिक खा या निगल जाते हैं और सांस के जरिए शरीर में पहुंचाते हैं।

लोगों द्वारा माइक्रोप्लास्टिक के निगले जाने का अधिक व्यापक अनुमान लगाने अध्ययन में हर एक देश की खाने की आदतों, खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों, आयु जनसांख्यिकी और सांस लेने की दर को ध्यान में रखा गया है। ये सभी कारण जो हर एक देश के निवासियों द्वारा माइक्रोप्लास्टिक के निगले जाने के तरीके में अंतर बताता है।

शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा कि हर देश के स्तर पर माइक्रोप्लास्टिक का बढ़ना प्लास्टिक प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाले खतरों का एक बड़ा इशारा है। एक बड़ा वैश्विक मानचित्रण पानी की बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण और प्रभावी कचरे की रीसाइक्लिंग के माध्यम से स्थानीय प्रदूषण को कम करने के प्रयासों में अहम भूमिका निभाता है।

अध्ययन फलों, सब्जियों, प्रोटीन, अनाज, डेयरी, पेय, शकज़रा, नमक और मसालों जैसे प्रमुख खाद्य उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा को लेकर आंकड़े एकत्रित करके आहार सेवन का आकलन करता है। मॉडल आंकड़ों का उपयोग यह बताने के लिए भी करते हैं कि विभिन्न देशों में उन खाद्य पदार्थों की कितनी खपत की जाती है। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया और अमेरिका में प्रति व्यक्ति टेबल नमक की खपत लगभग बराबर है, लेकिन इंडोनेशियाई नमक में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा लगभग 100 गुना अधिक है।

कुल मिलाकर, अध्ययन में पाया गया कि इंडोनेशियाई लोग हर महीने लगभग 15 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक खाते हैं। यह किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है, जहां अधिकांश प्लास्टिक कण समुद्री भोजन जैसे जलीय स्रोतों से आते हैं। यह 1990 से 2018 तक रोजमर्रा की माइक्रोप्लास्टिक खपत में 59 गुना वृद्धि है।

गर्म हवाओं एवं तापमान अधिक होने पर पशुओं को लू लगने का भी खतरा

गर्मी में पशुओं को लू से बचाने पालक इस तरह करें देखभाल

पशुपालक को मौसम में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने पशुओं का प्रबंधन करना चाहिए

भोपाल। इस समय पूरे देश में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। एसे में पशुओं की देखभाल विशेष तोर पर करनी चाहिए। पशुओं को लू से बचाने के लिए पशुपालकों को पर्याप्त प्रबंध करना चाहिए। दतिया के उपसंचालक डॉ. जी दास ने बताया कि पशुपालन व्यवसाय से जुड़े कृषक या उद्यमी को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि गर्मी के मौसम में अपने पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पशुपालक को मौसम में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने पशुओं का प्रबंधन करना चाहिए, जिससे उनके उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। गर्मी के मौसम में पशुओं के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्म हवाओं एवं तापमान अधिक होने पर पशुओं को लू लगने का भी खतरा बना रहता है।

पशुओं की उत्पादन क्षमता पर पड़ता है प्रभाव– अधिक तापमान होने पर गर्म लू के थपेड़े चलने लगते हैं तो जिससे पशु दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। इस दबाव की स्थिति का पशुओं की पाचन प्रणाली और दूध उत्पादन क्षमता पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। गर्मी में यदि नवजात पशुओं की उचित देखभाल ने की जाये तो इसका असर भविष्य में उनकी शारीरिक वृद्धि स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधी क्षमता और उत्पादन क्षमता पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। गर्मी में पशुपालन करते समय उनके प्रबंधन पर ध्यान न देने पर पशु के सूखा चारा खाने की मात्रा में 10 से 30 प्रतिशत और दूध उत्पादन क्षमता में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। साथ ही साथ अधिक गर्मी के कारण पैदा हुए आक्सीकरण तनाव की वजह से पशुओं की बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है और आगे आने वाले बरसात के मौसम में वे विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।

गर्मी में पशुओं को कौन सा आहार खिलाएं

» गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा अधिक खिलाना चाहिए, पशु इसे चाव से खाता है। हरे चारे में 70-90 प्रतिशत जल की मात्रा होती है, जो समय-समय पर पशु शरीर को जल की आपूर्ति भी करता है।

» गर्मी में पशुओं को भूख कम व प्यास अधिक लगती है। इसके लिए गर्मी में पशुओं को स्वच्छ पानी अथवा दिन में कम से कम तीन बार अवश्य पिलाना चाहिए। इससे पशु शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखने में मदद मिलती है।

» पानी में थोड़ी मात्रा में नमक व आटा मिलाकर पिलाना भी अधिक उपयक्त है। इससे अधिक समय तक पशु के शरीर में पानी की आपूर्ति बनी रहती है, जो शुष्क मौसम में लाभकारी भी है।

» गर्मी के समय में पशुओं को संतुलित आहार के साथ साथ हरे चारे की अधिक मात्रा उपलब्ध कराना चाहिए। इसके दो लाभ हैं। एक पशु अधिक चाव से स्वादिष्ट एवं पौष्टिक चारा खाकर अपनी उदरपूर्ति करता है। दूसरा हरे चारे में 70-90 प्रतिशत तक पानी की मात्रा होती है, जो समय-समय पर जल की पूर्तिकरता है।

» सामान्यतः गर्मी में मौसम में हरे चारे का अभाव रहता है। इसलिए पशुपालक को चाहिए कि गर्मीज के मौसम में हरे चारे के लिए मार्च, अप्रैल माह में मूंग, मक्का, काऊपी, चरी आदि की बोवनी कर दें जिससे गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके। ऐसे पशुपालन जिनके पास सिंचित भूमि नहीं है, उन्हें समय से पहले हरी घास काटकर एवं सुखाकर तैयार कर लेना चाहिए। यह घास प्रोटीन युक्त, हल्की और पौष्टिक होती है।

» गर्मी के दिनों में पशुओं को खनिज लवण देना लाभदायक रहता है, क्योंकि गर्मी के दबाव के कारण पशुओं के पाचन प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है और भूख कम हो जाती है। गर्मी के मौसम में पशुओं को भूख कम लगती है और प्यास अधिक इसलिए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में दिन में कम से कम तीन बार पानी पिलाना चाहिए। जिससे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

» इसके अलावा पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक एवं आटा मिलाकर पानी पिलाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में साफ सुथरा ताजा पीने का पानी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। पीने के पानी को छाया में रखना चाहिये। पशुओं से दूध निकालनें के बाद उन्हें यदि संभव हो सके तो ठंडा पानी पिलाना चाहिये। गर्मी में 3-4 बार पशुओं को अवश्य ताजा ठंडा पानी पिलाना चाहिए। पशु को प्रतिदिन ठंडे पानी से भी नहलाने की सलाह दी जाती है।

गर्मी के दिनों में पशुओं के आवास प्रबंधन

पशुपालकों को पशु आवास हेतु पक्के निर्मित मकानों की छत पर सूखी घास या कडवी रखें ताकि छत को गर्म होने से रोका जा सके। पशु आवास के अभाव में पशुओं को छायाकार पेड़ों के नीचे बांधे। पशु आवास में गर्म हवाओं का सीधा प्रवाह नहीं होने पाये इसके लिए लकड़ी के फटे या बोरी के टाट को गीला कर दें, जिससे पशु आवास में ठंडक बनी रहे। पशु आवास गृह में आवश्यकता से अधिक पशुओं को नहीं बांधे तथा रात्रि में पशुओं को खुले स्थान पर बांधे। सीधे तेज धूप और लू से पशुओं को बचाने के लिए पशु-शाला के मुख्य द्वार पर खस या जूट के बोरे का पदार्द लगाना चाहिये। पशुओं के आवास के आस पास छायादार वृक्षों की मौजूदगी पशु-शाला के तापमान को कम रखने में सहायक होती है। गाय, भैंस की आवास की छत यदि एस्बेस्टस या कंक्रीट की है तो उसके ऊपर 4-6 इंच मोटी घास-फूस की तह लगा देने से पशुओं को गर्मी से काफी आराम मिलाता है। इन उपायों और निर्देशों को अपना कर पशुपालक द्वारा अपने पशुओं की देखभाल उचित तरीके से की जा सकती है और गर्मी के प्रकोप से बचाया जा सकता है। उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

पशुओं को लू लगने के लक्षण

भीषण गर्मी की स्थिति में पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रबन्धन एवं उपाय करने की आवश्यकता होती है, जिनमें ठंडा एवं छायादार पशु आवास, स्वच्छ पीने का पानी आदि पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। वातावरण में नमी और ठंडक की कमी एवं पशु आवास में स्वच्छ वायु का ना आना, कम स्थान में अधिक पशु रखना और गर्मी के मौसम में पशु को पर्याप्त मात्रा में पानी न पिलाना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। लू लगने के कारण पशु को तेज बुखार आ जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है। पशुओं को आहार लेने में अरुचि, तेज बुखार, हांफना, मुँह से जीभ बाहर निकलना, मुँह के आसपास झाग आ जाना, आंख व नाक लाल होना, नाक से खून बहना, पतला दस्त होना, श्वास कमजोर पड़ जाना उसकी हृदय की धड़कन तेज होना आदि लू लगने के प्रमुख लक्षण हैं। लू लगने पर पशु सुस्त होकर खाना पीना बन्द कर देता है। शुरू में पशु की श्वसन गति एवं नाड़ी गति तेज हो जाती है। कभी-कभी नाक से खून भी बहने लगता है। पशु पालक के समय पर ध्यान नहीं देने से पशु की श्वसन गति धीरे धीरे कम होने लगती है एवं पशु चक्कर खाकर बेहोशी की दशा में ही मर जाता है।

पशुओं को लू लगने पर यह करें...

पशुपालक कुछ सावधानियां अपनाकर अपने पशुओं को लू से बचा सकते हैं। पशुपालक डेरी को इस प्रकार बनाये की सभी जानवरों के लिए उचित स्थान हो ताकि हवा को आने जाने के लिए जगह मिले ध्यान रहे की शेड खुला हवादार हो। लू लगने पर पशु को ठंडे स्थान पर बांधे तथा माथे पर बर्फ या ठंडे पानी की पट्टियां बांधे जिसमें पशु को तुरन्त आराम मिले। पशु को प्रतिदिन 1-2 बार ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। पशु के लिए पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
मवेशियों को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालक उनके आवास में पंखे, कूलर और फव्वारा सिस्टम लगा सकते हैं। दिन के समय में उन्हें अन्दर बांध कर रखें। लू की चपेट में आने और ठीक नहीं होने पर पशु को तुरंत पशुचिकित्सक या चलित पशु चिकित्सा इकाई 1962 पर फोन कर उपचार व सलाह ले सकते हैं। पशुओं को इलेक्ट्रोल देनी चाहिए।

जून में देश के 150 शहरों में पशुओं पर अटैक कर सकती हैं दो घातक बीमार

सबसे ज्यादा असर झारखंड, कर्नाटक और केरल-में देखने को मिलेगा

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

वैसे तो कई तरह की मौसमी बीमारियां ही पशुओं को परेशान करती रहती हैं। लेकिन कुछ घातक और जानलेवा बीमारियों का खतरा भी पशुओं पर लगातार बना रहता है। एनिमल एक्सपर्ट की मानें तो इसमे से कई ऐसी भी बीमारियां हैं, जिनका अभी तक कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन समय से वैक्सीनेशन कराने पर ऐसी बीमारियों से अपने पशुओं को बचाया जा सकता है। हाल ही में निवेदी संस्थान ने पशुओं की ऐसी ही दो घातक बीमारियों के बारे में अलर्ट जारी किया है। संस्थान के मुताबिक आने वाले जून में देश के 150 शहरों में दो घातक बीमारी पशुओं पर अटैक कर सकती हैं। संस्थान का कहना है कि दो दो बीमारियों का सबसे ज्यादा असर झारखंड, केरल और कर्नाटक में देखने को मिल सकता है। गौरतलब रहे निवेदी संस्थान हर महीने पशुओं की बीमारियों से संबंधित अलर्ट जारी करता है। संस्थान का दावा है कि उसके अलर्ट 90 फीसद से ज्यादा मामलों में सच साबित होते हैं।

पीपीआर और एफएमडी का हो सकता है अटैक

निवेदी संस्थान की ओर से जारी किए गए अलर्ट के आंकड़ों पर जाएं तो जून में वैसे तो 15 तरह की बीमारियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के मुताबिक देश के 742 शहरों में ये बीमारियां अपना असर दिखा सकती हैं। लेकिन इसमे से पीपीआर और खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। पीपीआर खासतौर से भेड़ और बकरियों को होने वाली बीमारी है। जबकि एफएमडी गाय-भैंस, भेड़-बकर आदि को होने वाली बीमारी है।

झारखंड में पीपीआर- एफएमडी का यहां हो सकता है असर

संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पीपीआर का 20 और एफएमडी का 17 शहरों पर असर देखने को मिल सकता है। एफएमडी की बात करें तो बोकारो, दुमका, गुमला, हाजारीबाग, कोडरमा, पाकुड़, कुंती, रामगढ़ और रांची आदि वैरी हाई रिस्क पर हैं। जबकि पीपीआर के मामले में जामताड़ा, पलामू, बोकारो, दुमका, गुमला, हाजारीबाग, कोडरमा, पाकुड़, कुंती, रामगढ़ और रांची आदि वैरी हाई रिस्क पर हैं।

कर्नाटक-केरल के शहर भी हैं वैरी हाई रिस्क पर

संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के 12 शहरों में एफएमडी और नौ शहरों में पीपीआर का असर देखने को मिल सकता है। वहीं केरल के 14 शहरों में एफएमडी और दो शहरों में पीपीआर के मामले देखने को मिल सकते हैं। दोनों राज्यों के ज्यादा शहर वैरी हाई रिस्कर पर हैं। कर्नाटक के बेलगूपर, चिकमंगलूहर, हासन, मैसूर आदि में बीमारी असर दिखा सकती है। वहीं केरल की बात करें तो कन्नूर, कोल्लम, एरनाकुलम, कोटायम, वायनाड और कोटय्यम आदि शहर भी वैरी हाई रिस्क पर हैं।

मुर्गियों में रानीखेत बीमारी
इसके लक्षण-बचाव के उपाय

भोपाल। जागत गांव हमार

गर्मी का मौसम मुर्गियों के लिए बहुत घातक होता है। ज्यादा गर्मी और लू की वजह से मुर्गियों में रोग पनपते हैं। इन्हीं रोगों में से एक रोग है रानीखेत है। यह एक संक्रमण रोग है, जो मुर्गियों में तेजी के साथ फैलता है। इस रोग की चपटे में आने से मुर्गियों की मौत हो जाती है। खास बात यह है कि रानीखेत रोग पहली पर 1926 में पता लगा था। रानीखेत रोग की चपेट में आने पर मुर्गियां सांस नहीं ले पाती हैं। इसके चलते 100 फीसदी तक मुर्गियों की मौत हो जाती है। वहीं, इस रोग से ग्रसित मुर्गियां अंडा देना बंद कर देती हैं। इस रोग के विषाणु 'पैरामाइक्सो' को सबसे पहले वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के 'रानीखेत' शहर में चिन्हित किया था। यही वजह है कि पैरामाइक्सो रोग का नाम रानीखेत रख दिया गया। यह रोग मुर्गियों के अलावा टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे और गिनी में भी तेजी से फैलता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बुरा असर मुर्गियों के ऊपर ही पड़ता है।

तेजी से फैलता है रोग

मुर्गियों में रानीखेत रोग किसी भी उम्र तक हो सकता है। इस रोग के लक्षण पहले से तीसरे सप्ताह में मुर्गियों के ऊपर दिखने लगता है। भारत में रानीखेत रोग के नमूने राज्यों के सभी भागों में देखने को मिलते है। लेकिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कनाडटक में यह रोग मुर्गियों में सबसे अधिक लगता है। इस रोग के कारण मुर्गी पालकों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि मुर्गियों की मौत हो जाती है। रानीखेत रोग एक मुर्गीज से दूसरी मुर्गी में तेजी से फैलता है।

रोग के लक्षण

एक्सपर्ट की माने तो संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु और उनके दूषित दाना, पानी आदि के स्पर्श से यह रोग एक मुर्गी से दूसरी मुर्गियों में फैलता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती हैं। रानीखेत रोग कुक्कुट-पालक को कई तरह से आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के चलते मुर्गियों का वजन कम हो जाता है। वह अंडा देना बंद कर देती हैं।

किसानों को ई-समृद्धि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा

अब एमएसपी पर मक्का भी बेंच सकेंगे किसान, पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन

भोपाल। जागत गांव हमार

मक्का की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसान अब अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकार को बेच सकेंगे। इसके लिए किसानों को ई-समृद्धि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसान अपनी उपज को उचित कीमत पर बेच सकेंगे।

कृषि मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। इसमें कहा गया है कि हर किसान का अधिकार है कि उसे उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। अब https://esamridhi.in/# पर पंजीकरण करें और अपने मक्के को उचित मूल्य पर बेचें।

ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

किसान मोबाइल से भी मक्का की बिक्री के लिए नेफेड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस बहुत ही आसान हैं।

- आपको सबसे पहले https://esamridhi.in/# वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन और एजेंसी रजिस्ट्रेशन दिखेगा।
- आप किसान हैं तो आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।
- यहां अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें।
- नेफेड पर मक्का बिक्री का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

ऐसे काम करता है पोर्टल

एक बार जब कोई किसान नए ई-समृद्धि प्लेटफार्म पर खुद को रजिस्टर करता है तो वह सभी खरीदे गए और रिजेक्टेड लॉट को रिकॉर्ड करता है। प्रत्येक लॉट के लिए एक यूनिक नंबर जारी करता है और इन्वेंट्री को अपडेट करता है। उपयोगकर्ता खरीदी गई वस्तुओं की सूची देख सकते हैं। सिस्टम प्रत्येक बैग को एक क्यूआर कोड के साथ टैग करता है, जिसे ई-समृद्धि खरीद पोर्टल के साथ मैप किया जाता है और इस प्रकार खरीद प्रक्रिया को आसान और सुव्यवस्थित किया जाता है, जिससे पारदर्शिता, सटीकता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। ई-समृद्धि प्लेटफार्म खरीद और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एकीकृत करता है, जिससे पीएनफएमएस प्रोसेस के जरिए किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है। किसान को डीबीटी के माध्यम से खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाता है। किसानों को बोनस भी दिया जाएगा। किसानों को समय पर बिना किसी परेशानी के सीधे उनके खातों में भुगतान से फायदा होता है।

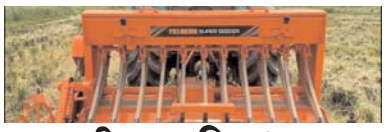

सुपर सीडर कृषि यंत्र पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है सरकार

भोपाल। सुपर सीडर ट्रैक्टर के साथ जुड़कर कार्य करने वाला ऐसा यंत्र है जो फसल अवशेषों (नरवाई/पराली) की समस्या का निदान करने के साथ-साथ बुवाई भी करता है। जो किसान धान की खेती के बाद गेंहू और चने की बुवाई करते हैं उनके लिए यह अत्यंत उपयोगी है। सुपर सीडर से नरवाई वाले खेत में सीधे गेंहू, चने अथवा अन्य फसल की बोवनी की जा सकती है। इसके उपयोग से किसान को नरवाई की झंझट से मुक्ति मिलती है। जो नरवाई किसान के लिए समस्या है उसे सुपर सीडर खाद के रूप में बदलकर वरदान बना देता है।

सरकार दे रही है सब्सिडी

एमपी में किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत सुपर सीडर खरीदने पर 40 से 50 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। सुपर सीडर सामान्य तौर पर एक घण्टे में एक एकड़ क्षेत्र में नरवाई नष्ट करने के साथ बुवाई कर देता है। गेंहू के बाद जिन क्षेत्रों में मूंग की खेती की जाती है वहाँ भी सुपर सीडर बहुत उपयोगी है। हार्वेस्टर से कटाई के बाद गेंहू के शेष बचे डंठल को आसानी से मिट्टी में मिलाकर सुपर सीडर मूंग की बुवाई कर देता है। बता दें एमपी में किसानों को सभी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए M P Kisan App या kisan.mp.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किसान यह रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, खसरा बी-वन की नकल, समग्र आईडी, मोबाइल नम्बर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेजों की मदद से करा सकते हैं।

योजना का लाभ उठाने पर किसानों को सालाना 6 लाख रुपए तक की बचत

एग्री इंफ्रा फंड योजना किसानों के लिए वरदान, लाभ लेने के लिए करें आवेदन

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों को लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है, जिसका नाम एआईएफ यानी कृषि अवसंरचना कोष योजना है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान सालाना 6 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं।

कृषि अवसंरचना कोष योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोल्ड स्टोर, वेयरहाउसिंग, साइलो, पैकिंग यूनिट्स, परख/ग्रेडिंग, लॉजिस्टिक फैसिलिटी, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर और रिपेनिंग रूम/वैक्सिंग प्लांट आदि स्थापित करना है ताकि फसल कटाई के बाद अच्छे से प्रबंधन किया जा सके।

योजना से लाभ- कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत लोन लेने पर ब्याज में तीन फीसदी छूट मिलती है। वही ब्याज पर यह छूट अधिकतम 7 सालों तक मिलती रहती है यानी दो करोड़ लोन लेने पर 7 सालों तक सालाना 6 लाख रुपए तक की बचत होती रहती है। इस लोन पर सिक्योरिटी भी सरकार ही देती है। वही कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत अधिकतम दो करोड़ तक लोन मिल सकता है। हालांकि, जरूरत के अनुसार और ज्यादा और कम लोन लिया जा सकता है। इसके

अलावा किसानों को उचित समय पर उचित कीमत मिलती है। भंडारण की बेहतर सुविधा होने की वजह से फसलों की बर्बादी भी कम होती है। नतीजतन, सालाना होने वाले नुकसान से किसानों को राहत मिलती है और आमदनी में बढ़ोतरी होती है।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ

कृषि अवसंरचना कोष योजना का लाभ देश के सभी राज्यों के किसान उठा सकते हैं। इसके अलावा कृषि उपज बाजार समिति, एग्री एंटरप्रेन्योर, किसान उत्पादक संगठन,कृषक उपज संगठनों का संघ, संयुक्त दायित्व समूह, विपणन सहकारी समिति, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय संघ, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूहों के संघ, राज्य की एजेन्सियां, सहकारी समितियों के राज्य संघऔर स्टार्ट-अप भी लाभ उठा सकते हैं।

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

- आवेदन फार्म
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- आईडी प्रमाण जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट
- पते का प्रमाण जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)
- मूल स्वामित्व विलेख, गृह/संपत्ति कर भुगतान रसीदें। बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार शीर्षक जांच रिपोर्ट (टीआईआर)

आवेदन प्रक्रिया

- आवेदक सबसे पहले www.agriinfra.dac.gov.in पर विजिट कर आवेदन करें।
- दो दिनों के भीतर आवेदक के पास कृषि मंत्रालय द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा।
- इसके बाद आगे की जरूरी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें।
- आपका आवेदन ऑटोमेटिक आप द्वारा फार्म में भरे गए बैंक में चला जाता है।
- बैंक द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद, आपके फोन पर मैसेज द्वारा पूरी जानकारी मिल जाएगी।

खुशखबरी! पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बढेंगी राशि सरकार ने शुरू की कवायद

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में किसानों के आर्थिक विकास के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत पीएम किसान योजना का मूल्यांकन करने की योजना बनाई है। नीति आयोग से जुड़े विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय ने इस योजना के मूल्यांकन के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। बता दें कि इस योजना की लागत सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 60,000 करोड़ रुपए है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि इसका मकसद यह मूल्यांकन करना है कि योजना ने किस हद तक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा किया। इसके साथ ही कृषि आय पर इसका कितना प्रभाव पड़ा। यह भी समझना कि क्या डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर (डीबीटी) किसानों के लिए एक आदर्श तरीका है

या नहीं। अधिकारी ने कहा- योजनाओं के मूल्यांकन की समय अवधि छह महीने होगी। योजना मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षण में 24 राज्यों के न्यूनतम 5000 किसानों को शामिल किया जाएगा, जिनमें से शीर्ष 17 राज्य हैं। वहीं, लगभग 95 प्रतिशत पीएम किसान लाभार्थी हैं।

पीएम किसान योजना क्या है?

गौरतलब है कि पीएम किसान एक केंद्रीय डीबीटी योजना है, जिसके तहत देशभर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह रकम 2000 रुपए की तीन किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। सरकार ने 2024-25 में इस योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष के बजट और संशोधित अनुमान के बराबर है। 2022-23 में योजना के कुल 10 करोड़ 71 लाख लाभार्थी थे।

दानों में खनिज पदार्थों की मात्रा बाकी अनाज फसलों से ज्यादा

रागी की वैज्ञानिक की खेती किसानों के लिए लाभदायक

भोपाल। जागत गांव हमार

रागी की खेती मोटे अनाज के रूप में की जाती है। रागी मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में उगाई जाती है। जिसको मडुआ, अफ्रीकन रागी, फिंगर बाजरा और लाल बाजरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधे पूरे साल पैदावार देने में सक्षम होते हैं। इसके दानों में खनिज पदार्थों की मात्रा बाकी अनाज फसलों से ज्यादा पाई जाती है। रागी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पायी जाती है, जिसका उपयोग करने पर हड्डियां मजबूत होती है। रागी बच्चों एवं बड़ों के लिए उत्तम आहार हो सकता है। प्रोटीन, वसा, रेषा, व कार्बोहाइड्रेट इसमे प्रचुर मात्रा में पाये जाते है। महत्वपूर्ण विटामिन जैसे थायमीन, रिबोफ्लेविन, नियासिन एवं आवश्यक अमीनों अम्ल की प्रचुर मात्रा पायी जाती है, जोकि विभिन्न शारीरिक क्रिक्रयाओं के लिए जरूरी होते हैं। कैल्शियम व अन्य खनिज तत्वों की प्रचुर मात्रा होने के कारण ओस्टियोपोरोसिस से संबंधित बीमारियों तथा बच्चों के आहार (बेबी फूड) के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है।

बीज का चुनाव मृदा की किस्म के आधार पर करें। जहां तक संभव हो प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। यदि किसान स्वयं का बीज उपयोग में लाता है तो बोवनी पूर्व बीज साफ करके फफूंदनाशक दवा (कार्वेन्डाजिम/ कार्वोक्सिन/ क्लोरोथेलोनिल) से उपचारित करके बोये। रागी की सीधी बोवनी अथवा रोपा पद्धति से बोवनी की जाती है। सीधी बोवनी जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है। छिंटवा विधि या कतारों में बोनी की जाती। कतार में बोआई करने के लिए बीज दर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर एवं छिंटवा पद्धति से बोवनी करने पर बीज दर 12-15 किलो प्रति हेक्टेयर रखते है। कतार पद्धति में दो कतारों के बीच की दूरी 22.5 सेमी एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखे। रोपाई के लिए नर्सरी में बीज जून के मध्य से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक डाल देना चाहिए। एक हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए बीज की मात्रा 4 से 5 किलो लगती है। 25 से 30 दिन की पौध होने पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के समय कतार से कतार व पौधे से पौधे की दूरी क्रमश: 22.5 सेमी. व 10 सेमी. होनी चाहिए।

बीज चयन| उन बीजों का चयन करें जो उचित वातावरण और मिट्टी में अच्छे प्रकार के अनुकूल हों। अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना उचित होता है।

कब करें बोवनी| बीजों को समय अनुसार बोवनी करें ताकि उत्तम उत्पादन हो सके। रागी को मुख्य रूप से गर्मियों में बोया जाता है। बीज को बोवनी का सबसे उत्तम समय मार्च से जून तक होता है। यह समय रागी के उत्तम पौधों के विकास के लिए उत्तम होता है।

सिंचाई| नियमित सिंचाई करें, विशेष रूप से पौधों के विकास के समय में, ताकि उत्तम फलन हो। रागी के बीजों को बोवनी से पहले मिट्टी की उचित तैयारी करें। उपयुक्त खाद और मिट्टी के मिश्रण का उपयोग करें ताकि पौधों को अच्छी ग्रोथ मिल सके। बीजों को बोवनी के बाद, उन्हें नियमित सिंचाई दें ताकि वे अच्छी तरह से उगें।

रागी की उन्नत किस्में| बीएल-376- बीएल रागी (मडुआ) 376 किस्म रागी की एक उत्तम किस्म है। इसकी उपज क्षमता 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। बीएल रागी 146- बीएल रागी 146 किस्म अगेती की सबसे अच्छी किस्म है। इसकी उपज क्षमता 10-11 क्विंटल प्रति एकड़ तक होती है। बीएल 124 - बीएल 124 किस्म रागी की एक बेहतर किस्म है।

कटाई और मढ़ाई| रागी के पौधे बीज रोपाई के लगभग 110 से 120 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद इसके सिरों को पौधों से काटकर अलग कर लें। सिरों की कटाई करने के बाद उन्हें खेत में ही एकत्रित कर कुछ दिन सूखा लें। उसके बाद जब दाना अच्छे से सूख जाए तब मशीन की सहायता से दानों को अलग कर एकत्रित कर बोरों में भर लें।

खरपतवार नियंत्रण रागी की खेती में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है। रासायनिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए बीज रोपाई के पहले आइसोप्रोट्यूरॉन या ऑक्सीफ्लोरफेन की उचित मात्रा का छिड़काव खेत में कर दें। जबकि प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण पौधों की निराई गुड़ाई कर किया जाता है। इसके लिए शुरुआत में पौधों की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उनकी पहली गुड़ाई कर दें। रागी की खेती में प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए दो बार गुड़ाई काफी होती है। इसलिए पहली गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों की एक बार और गुड़ाई कर दें।

काले मक्के की खेती किसानों के लिए फायदेमंद

काले मक्के से हो जाएगा कुपोषण का खात्मा

भोपाल। जागत गांव हमार

मक्का की खेती कई वजह से किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। मक्का की सफेद व लाल किस्म के अलावा बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती के प्रति किसानों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। अब जायद सीजन में बोवनी के लिए काली मक्का की खेती किसानों द्वारा पसंद की जा रही है। मक्के की यह किस्म कुपोषण से लड़ने में कारगर है। इसमें आयरन, कॉपर और जिंक अधिक मात्रा में मिलता है। यह मक्का की पहली किस्म है जो न्यूट्रीरिच और बायो फोर्टिफाइड है। इस किस्म का भुट्टा बाजार में महंगे दाम पर मिलता है। सामान्य मक्का की तुलना में इसका भाव हमेशा ज्यादा मिलता है, क्योंकि बहुत कम किसान इसकी किस्म की खेती करते हैं। काली मक्का की खेती में कौनसी किस्म का बीज बोना चाहिए? इसकी जानकारी हर किसान को होनी चाहिए। काली मक्का की खेती पर देश में पहली बार छिंदवाड़ा के कृषि अनुसंधान केंद्र ने रिसर्च किया और मक्का की नई प्रजाति जवाहर मक्का 1014 विकसित की। कृषि वैज्ञानिक अब इस किस्म को लगाने की सलाह देते हैं। मक्का की यह किस्म अपने पोषक तत्वों के कारण कुपोषण से लड़ने में कारगर साबित होगी। कई स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों में इस उपयोग संभव हो सकेगा।

जवाहर मक्का 1014 से कितनी मिलेगी पैदावार

कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की यह प्रजाति मध्यप्रदेश के लिए अनुशंसित की है। किसान एक एकड़ जमीन में 8 किलो बीज से 26 क्विंटल तक पैदावार ले सकता है। मक्का की यह किस्म 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी सिल्क 50 दिन में आती है। काले मक्का की फसल के अच्छे विकास के लिए अधिक गर्म मौसम की जरूरत होती है। जब इसके पौधे पर भुट्टे तैयार होने लगते हैं तब अधिक पानी की जरुरत होती है। इसकी खेती कतार में की जाती है और कतार में पौधे से पौधे की दूरी 60 से 75 सेमी होनी चाहिए। मक्का की यह प्रजाति तना छेदक रोग के प्रति सहनशील है। वर्षा आधारित पठारी क्षेत्र के लिए यह किस्म अधिक उपयुक्त है।

मिलेगा शानदार स्वाद और अधिक पौष्टिकता

काली मक्का अपने स्वाद और अधिक पौष्टिक गुणों के कारण धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही है। पीली और सफेद मक्का के पत्तों का रंग हरा होता है, लेकिन काली मक्का के पत्तों का रंग हल्का बैंगनी होता है। काली मक्का का भुट्टा 20 से 25 सेमी तक लंबा होता है। इनके पौधों की लंबाई 2.5 मीटर से 3 मीटर तक होती है। काली मक्का के दानों में स्टार्च अधिक होता है। इस किस्म की मक्का के पौधे पर भुट्टे में जब दाने तैयार होने लगते हैं तब काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। यह भुट्टे एक तरह का पदार्थ छोड़ते हैं और इन पर दाग लगना शुरू हो जाता है। इन दागों को हाथों से हटाया जा सकता है। काली मक्का के दानों को पकने में अधिक समय लगता है। पकने के बाद इसके दाने काले, चमकीले और आकर्षक दिखाई देते हैं। काली मक्का के दाने पीली व सफेद मक्का की तुलना में अधिक स्वादिष्ट और मीठे होते हैं। कुल मिलाकर, ब्लैक कॉर्न स्वादिष्ट होने के साथ ही पोषक तत्वों से भी भरपूर है जिसका उपयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी फायदेमंद है। अभी तक हमारे देश में किसान सफेद और पीली मक्का की खेती कर रहे हैं, लेकिन काली मक्का की खेती के प्रति भी किसानों का रुझान बढ़ रहा है।

किसान ग्वार की खेती कब और कैसे करें, जान लें विधि

ग्वार को औद्योगिक फसल का दिया गया दर्जा

भोपाल। जागत गांव हमार

ग्वार एक दलहनी फसल है, ग्वार प्रमुख रूप से चारे एवं दाने की फसल के रूप में उगाई जाती है। इसके दानों से गोंद भी तैयार किया जाता है। ग्वार का वैज्ञानिक नाम 'साया मोटिसस टेट्रागोनोलोबस'। ग्वार की खेती विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और कर्नाटक के शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। यह फ कम पानी में भी अच्छी तरह से उग सकती है, इसलिए यह सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक आदर्श फसल मानी जाती है। ग्वार की खेती के लिए ज्यादातर हल्की बलुई या दोमट मिट्टी प्रभावी रहती है, जिसमें अच्छी जल निकासी की सुविधा हो। इसकी बुवाई आमतौर पर मानसून के शुरुआती दौर में की जाती है। ग्वार की फसल को अत्यधिक नमी और अत्यधिक सूखे दोनों की स्थिति में नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए सिंचाई के प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ग्वार के बीजों में अत्याधिक प्रोटीन (40-45 प्रतिशत) तथा उच्च गुणवत्ता वाला गैलेक्टोमैनन नामक ग्वारगम मिलने के कारण ग्वार को औद्योगिक फसल का दर्जा दिया गया है।

ग्वार की उन्नत किस्में - एच जी -365, एच जी -563, आर जी सी -1066, आर जी सी -1003, पूसा नवबहार, एच एफजी -119, एच एफजी -156

कब करें बोवनी ग्वार की बोवनी का उचित समय जून का दूसरा पखवाड़ा माना जाता है। ऐसे में सिंचित क्षेत्रों में जब भी पानी उपलब्ध हो तो किसान ग्वार की बोवनी शुरू कर सकते हैं। बोवनी से पहले बीजों को उपचारित करके और इसके बाद ही बीजों की बुवाई करें। ग्वार की फसल को जड़ गलन जिसे उखेड़ा रोग भी कहते हैं इसकी रोकथाम के लिए 3 ग्राम कार्बन्डाजिम 50 प्रतिशत (बेविस्टीन) प्रतिकिलो बीज की दर से 15 से 20 मिनट सूखा उपचारित करने के बाद ही बीजों की बोवनी करनी चाहिए।

कैसे करें ग्वार की खेती

ग्वार की खेती ग्रीष्म और वर्षा दोनों ऋतुओं में की जा सकती है। इसे काली मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। ग्वार की बेहतर पैदावार के प्राप्त करने के लिए इसे बलुई दोमट मिट्टी में उगाना ज्यादा अच्छा रहता है। यदि सब्जी के लिए ग्वार की खेती कर रहे हैं तो इसे फरवरी-मार्च में सरसों, गन्ना, आलू के खाली पड़े खेतों में बोया जा सकता है। वहीं यदि चारे व दाने के लिए इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसे जून-जुलाई माह में बोना चाहिए। ग्वार की बोवनी प्रथम मानसून के बाद जून या जुलाई में की जा सकती है। ग्वार की बोवनी के लिए 5 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हैक्टेयर की जरूरत होती है। बोवनी से पहले ग्वार के बीजों को राईजोबियम व फॉस्फोरस सोलूबलाइजिंग बैक्टीरिया (पीएसबी) कल्चर से उपचारित करके बोना चाहिए।

मल्टीप्लेक्स के विक्रेता सम्मेलन में कंपनी के एमडी महेश शेट्टी ने कहा-किसानों की आय होगी दोगुनी

ई-ड्रोन से छिड़काव करने पर रसायन की 30 फीसदी बचत

भोपाल। जागत गांव हमार

विकसित भारत के लिए नए जमाने के उर्वरकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे सरकारी सब्सिडी बचेगी, जो इम्पोर्ट के कारण विदेशों में जा रही है। ई-ड्रोन से छिड़काव करने पर 30 फीसदी रसायन की बचत होती है। साथ ही पानी भी कम लगता है। इससे फसल पर समान छिड़काव होता है। पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। यह बात मल्टीप्लेक्स ग्रुप ऑफ कम्पनी के एमडी महेश शेट्टी ने गत दिवस इंदौर में विक्रेता सम्मेलन के दौरान कही। इस मौके पर कम्पनी के चीफ मार्केटिंग मैनेजर नागेंद्र शुक्ला, स्टेट मैनेजर सुनील पांडेय और बड़ी संख्या में डीलर व विक्रेता मौजूद रहे। वहीं कम्पनी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में सर्वाधिक बिक्री करने वाले विक्रेताओं को सम्मानित भी किया गया। कम्पनी के एमडी महेश शेट्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 15 हजार एकड़ में ड्रोन से किए गए छिड़काव के अच्छे नतीजे मिले हैं। नए उत्पादों पर उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा ट्रैक्टर निर्माण अभी प्रक्रिया में है, जबकि ड्रोन दीदियों और बड़े उर्वरक डीलरों के लिए ऑटोमेटिक ट्रॉली व्हीकल व बहुउद्देशीय जेसीबी मशीन भी लाए हैं, जो बहुत मददगार साबित होगी। कम्पनी के नए उत्पाद प्रणाम सीए पर भी प्रकाश डालते हुए शेट्टी ने बताया कि, जो कैल्शियम नाइट्रेट का विकल्प है और वो पूर्ण रूप से जैविक पदार्थ से बना खाद है।

» नए जमाने के उर्वरकों को प्रोत्साहित करने से बचेगी सब्सिडी

» सर्वाधिक बिक्री करने वाले विक्रेताओं को कंपनी ने नवाजा

किसानों के हित में कम लागत वाली खेती को प्रोत्साहित करने का आह्वान

शेट्टी ने समारोह के दौरान किसानों के हित में कम लागत वाली खेती को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया, ताकि विकसित भारत में किसानों की आय दोगुनी हो सके। कम्पनी के चीफ मार्केटिंग मैनेजर नागेंद्र शुक्ला ने ग्रीन फर्टिलाइजर की जानकारी देते हुए बताया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जहां जमीन कठोर हो रही है, वहीं खेती की लागत भी बढ़ रही है। जहरीले रसायनों से जमीन के अलावा मानव का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में ग्रीन फर्टिलाइजर को अपनाना समय की जरूरत है। यह रासायनिक खादों का बेहतर विकल्प भी है। इसके पूर्व विजय चौधरी ने कंपनी और उत्पादों की जानकारी दी।

समर्थन खरीदी केंद्र पर अच्छी उपज लाने वाले किसानों को नवाजेगी राज्य सरकार

-सीएम ने की कृषि आदान की समीक्षा, बोले-खाद की न हो कालाबाजारी

-प्रदेश में खरीफ के लिए सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो उर्वरक

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि खरीफ के लिए सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी कालाबाजारी की संभावना निर्मित न हो।

प्रदेश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से निरंतर सम्पर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषकों को संतुलित उर्वरक एनपीके के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में कृषि आदान की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव सहकारिता दीपाली रस्तोगी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में यूरिया, डीएपी, एनपीक, एसएसपी और एमओपी उर्वरक की मांग, अब तक प्राप्त मात्रा तथा वितरण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की।

बैठक में धान, कोदो, कुटकी, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास आदि के बीज की उपलब्धता की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फसल उपार्जन में अच्छी गुणवत्ता की पैदावार लाने वाले किसानों को सम्मानित व पुरस्कृत करने की प्रक्रिया भी आरंभ की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खाद के उपयोग को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए।

गौ-संरक्षण के लिए ग्राम स्तर पर करें पहल

बॉयो फर्टिलाइजर का उपयोग करने वाले किसानों की मदद के लिए व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे कृषक ऑर्गेनिक उत्पाद लेने के लिए आगे आएं। पशुपालन-कम्पोस्टिंग को समन्वित करते हुए श्रीअन्न की उपज लेने के लिए भी किसानों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। इससे फसल चक्र को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी और भूमि की उर्वरकता भी लंबे समय तक बनी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौ-वंश की सुरक्षा और उनकी उचित देखभाल के लिए गौ-सेवा संगठनों, सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं के साथ ग्राम स्तर पर पहल की जाए।

किसानों के लिए अल्पकालीन फसल ऋण की बढ़ाई तारीख

» फसल ऋण की राशि 31 मई तक होगी जमा

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश सरकार ने किसानों की फसल ऋण जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। किसान अब 31 मई तक ऋण जमा कर सकेंगे।

पहले ऋण जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा।

मध्य प्रदेश ने केवल उपार्जन से संबंधित कृषकों के लिए खरीद सीजन में वितरित किए गए अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि बढ़ाकर 31 मई नियत की है। सरकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर योजना की निरंतरता के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

आदेश में कही ये बात

विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसानों को किसानों को फसल की राशि मिलने में हो रही देरी के चलते राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि केवल ऐसे किसान जिन्होंने निर्धारित ड्यू डेट 30 अप्रैल तक समर्थन मूल्य पर अपनी फसलें बेची हैं और उन्हें उनकी उपज विक्रय की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे में उपार्जन की निर्धारित अंतिम तिथि तक फसलों का विक्रय करने वाले शेष किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजनान्तर्गत खरीफ 2023 सीजन की निर्धारित ड्यू डेट बढ़ाकर 31 मई की जाएगी।

उत्पादन वृद्धि पर्याप्त नहीं, हमें प्रसंस्करण पर काम करना होगा

पंचायत मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने की आजीविका मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों पर चर्चा

हमारे पास अपार क्षमता, इसका उपयोग करने की जरूरत

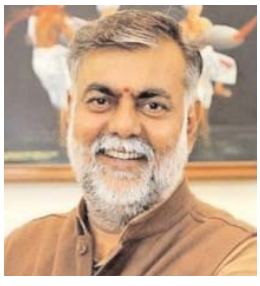

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के तहत किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किए जाने वाले गणवेश की गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इसी के साथ ही गणवेश की सिलाई के लिए उचित प्रशिक्षण भी समूह की महिलाओं को दिया जाए। इसे और अधिक मानकीकृत बनाने के लिए टैक्सटाइल आधारित स्टार्ट अप्स को इसमें शामिल करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पाद सिर्फ लोकल स्तर तक सीमित न रहे, उन्हें देश एवं विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उनकी ब्रांडिंग की जाए और ई मार्केट के माध्यम से उनकी बिक्री कराई जाए। हमारे पारंपरिक उत्पादों को अभी भी उनकी उचित पहचान नहीं मिल पाई है। हमारे पास अपार क्षमता है, हमें इसे सुसज्जित रूप से उपयोग करने की जरूरत है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को यदि कोई संबल प्रदान कर सकता है तो वह हमारे देश की महिलाएं ही है, उन्हें उनकी क्षमताओं का विस्तार करने में आजीविका मिशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और हमें इसे और बल प्रदान करना है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)